IREF
INDIAN RAILWAY EMPLOYEES FEDERATION

Affilated With: All India Central Council of Trade Unions (AICCTU)
Recognized by: Ministry of Labour & Employment, Govt. of India

Head Office : Block Extra 31/A-02, Trilokpuri, New Delhi, 110091 | gmail- iref.railway@gmail.com | Web: iref.railway.org

National President
Akhilesh Pandey
+9194557-92677

National Gen. Secretary
Sarvjeet Singh
+9176960-46087

No: IREF/RB/2025/005

Dated: 08/02/2026

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
रेलवे बोर्ड, रेल भवन,
नई दिल्ली – 110001

विषय: 12 फरवरी 2026 की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के नैतिक समर्थन एवं रेल कर्मचारियों की ज्वलंत मांगों के संबंध में सूचना।

महोदय,

इंडियन रेलवे एम्पलाइज फेडरेशन (IREF) आपको सूचित करना चाहती है कि देश की सभी प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा केंद्र सरकार की मजदूर/कर्मचारी/किसान विरोधी और निजीकरण/पूंजीवादी की नीतियों के खिलाफ आगामी 12 फरवरी 2026 को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल का इंडियन रेलवे एम्पलाइज फेडरेशन पुरजोर नैतिक समर्थन करती है। इस कड़ी में IREF से जुड़ी तमाम जोनल यूनियनों द्वारा इस दिन भारतीय रेलवे के विभिन्न मंडलों, कार्यशालाओं (Workshops) और उत्पादन इकाइयों (Production Units) में गेट मीटिंग, धरना-प्रदर्शन और विरोध रैलियों के माध्यम से अपना कड़ा रोष प्रकट किया जाएगा। रेल कर्मचारियों में भारतीय रेलवे में थोपी जा रही पूंजीवादी नीतियों को लेकर भारी असंतोष है।फेडरेशन का मानना है कि भारतीय रेलवे आज एक गंभीर संकट से गुजर रही है, जहाँ एक ओर रिक्त पदों के कारण कर्मचारियों पर काम का बोझ असहनीय स्तर तक बढ़ गया है, वहीं दूसरी ओर रेलवे की बुनियादी सेवाओं को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सुरक्षित रेल परिचालन के लिए जरूरी सुरक्षा उपकरणों की गुणवत्ता और कर्मचारियों की कार्य-परिस्थितियों की अनदेखी की जा रही है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, IREF मांग करती है कि रेलवे बोर्ड रेल कर्मचारियों की निम्नलिखित प्रमुख मांगों पर तत्काल विचार करे और सकारात्मक कदम उठाए ताकि औद्योगिक शांति बनी रहे। हमारी प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

1. NPS/UPS को निरस्त किया जाए और पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बिना किसी शर्त के तुरंत बहाल किया जाए।
2. रेलवे में निजीकरण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आउटसोर्सिंग, आफलोडिंग, ठेकेदारी प्रथा और मुद्रीकरण (Monetization) जैसी नीतियों पर पूरी तरह रोक लगाई जाए।
3. रेलवे में खाली पड़े लगभग 3 लाख से अधिक पदों पर स्थायी भर्ती की तत्काल व्यवस्था की जाए ताकि कार्यभार कम हो और संरक्षा (Safety) सुनिश्चित हो सके।
4. मजदूरों और कर्मचारियों के अधिकारों का हनन करने वाले 'चार श्रम कोड' (Four Labour Codes) को तुरंत रद्द किया जाए।
5. बढ़नी महंगाई को देखते हुए कर्मचारी के मूल वेतन का 20% अंतरिम राहत दी जाए।
6. सहायक लोको पायलट (ALP) और रनिंग स्टाफ के कार्य के घंटों को कम किया जाए और उनकी ड्यूटी की प्रस्थितियों में सुधार किया जाए।
7. ट्रैक मेंटेनर्स और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए रिस्क अलाउंस बढ़ाया जाए और उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाले सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।
8. रेलवे अस्पतालों और कॉलोनियों की बदहाल व्यवस्था को सुधारने के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया जाए।

... 2/-

अंत में, हम आपसे अपील करते हैं कि ब्रेटेन जैसे देशों के निजीकरण के असफल अनुभव से सीखते हुए न सिर्फ भारतीय रेलवे का निजीकरण रोका जाए बल्कि कर्मचारियों की सभी जायज मांगों को पूरा किया जाए। ताकि भारतीय रेलवे के कर्मचारियों को देश व्यापी हड़ताल पर जाने की नौबत न आए। बहरहाल इंडियन रेलवे इम्प्लाईज फेडरेशन भारतीय रेलवे एवं देश गंभीर हालातों के मध्य नजर 12 फरवरी 2026 की देशव्यापी आम हड़ताल का नैतिक समर्थन करते हुए पूरी भारतीय रेलवे में रोष प्रदर्शन कर संघर्ष लोगों के साथ अपनी एक जुटता प्रकट करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि रेलवे बोर्ड इन प्रस्थितियों को गंभीरता से लेगा और रेल कर्मचारियो के व्यापक हित में उचित निर्णय लेगा।

08-02-2026

(सर्वजीत सिंह)
राष्ट्रीय महासचिव/IREF

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. महासचिव, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन।
2. All President & Secretary of zonal Railways affiliated to IREF